

सम्पादकीय

कैसे बरकरार रहे लोकतंत्र की शोभा

हमसे लड़ने की हिम्मत तो रह गई ह। राजनीतिक दल जुटा लोगे लेकिन कमीनापन अक्सर चुनाव के बत्त इन्हें कहां से लाओगे? फौजियों का एक-दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल गोश्ठ कौवों को खिलायेंगे। करते हैं। श्री तोमर के बेटे के जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें फिल्म चाँझना गेट के ये संवाद शुरुआती दो वीडियो में पहले हैं। जिन्हें फिल्म में जीरा का किरदार निभाने वाले अभिनेता मुकेश तिवारी ने भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्णीय की चुनावी सभा में सुनाया। इस पर सभा में उपर्युक्त लोगों ने तो तालियां बजाई ही, खुद भाजपा प्रत्याशी भी इस पर ताली बजाते दिखे। फिल्म में प्रधृष्टि में ये संवाद बोले गए, वो अलग बात है, मगर चुनाव प्रचार में संवादों के बोले जाने पर सियासी खड़ेखाड़ा खड़ा हो गया है। कांगेस ने इन संवादों पर सवाल उठाए और कहा कि इन मुण्डों की हरें जरूरत नहीं, ये भाजपा को ही मुबारक। तो भाजपा ने पलटवार कर दिया कि अब कांगेस फिल्मी संवाद में भी राजनीति तलाश रही है। भाजपा और कांगेस के तर्कों में कौन सही है और कौन गलत, ये तथ्य करने का काम चुनाव आयोग का है, बशर्ते ये मामला आयोग तक पहुंचे।

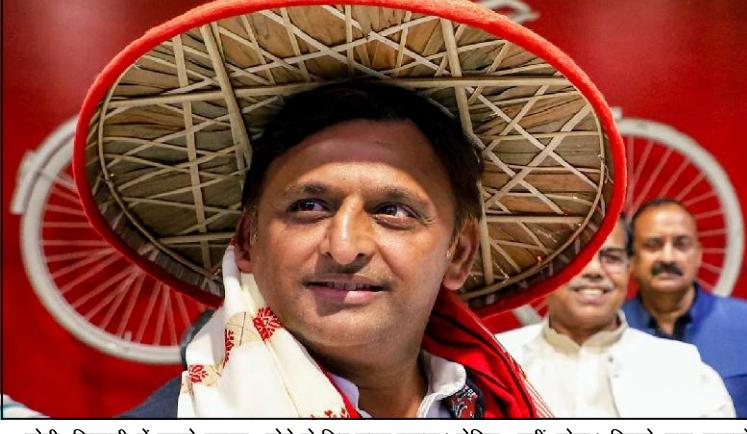
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए अब चुनाव प्रचार बन्द हो चुका है। 17 नवम्बर को छत्तीसगढ़ की शेष 30 सीटों व पट्टी प्रदेश की सभी 230 सीटों के लिए इन राज्यों के मतदाता अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करके अपनी मनमाफिक नामांकित दल की सरकार का गठन करेंगे। दोनों ही राज्यों में असांतों मुकाबला कांग्रेस व भाजपा के बीच हो रहा है और शेष सभी छोटी-मोटी पार्टियों को 'वोट कुड़ा' माना जा रहा है। चुनावों में मतदाता जिस वोट के अधिकार का प्रयोग करते हैं वह स्वतन्त्र समग्र महानायक महालम्प गांधी द्वारा उन्हें दिया गया वेशकीमीती अहिंसक हृथियार है जिस पर भारत का पूरा लोकतन्त्र टिका हुआ है। अब वोट का अधिकार इस देश के लोगों को अपनी पुराणी पीढ़ियों की कुबुंगी देने के बाद जिसा है व्यापक उहोंने न केवल भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी थी बल्कि आम भारतीय के स्वामिगण और जनागरिक समाज की लड़ाई भी लड़ी थी। महान्‌गांधी ने 1934 में ही खाली साल कर थी कि स्वतन्त्र भारत में इसके प्रत्येक वयस्क स्त्री—पुरुष नागरिक को एक वोट का अधिकार देकर संसदीय प्रणाली का लोकतन्त्र अपनाया जायेगा। इससे पहले प॑. मोर्डोन हेलू की सदारत में कांग्रेस पार्टी की गठित संसद समिति ने अपनी रिपोर्ट में सापू कर दिया था कि भारत में राज्यों के संघीय ढांचे के तहत प्रदेशों व केंद्र के अधिकार अलग—अलग हो गए औं इनकी सरकारों का गठन हर पांच साल के लिए प्रत्येक अमीर—गृही बी—हिन्दू—मुसलमान, मजदूर—जूंजीपति, शिक्षित—अनन्पद वयस्क को एक वोट का अधिकार देकर

बोस व व मौलाना आजाद भी उन्हें थे। मगर 1935 में जब योस्तान की हुक्मत पर कविज और संस्कृत एवं अंग्रेजी शब्दों का लगाया और 11 एसेंबलियों द्वारा बनाया गया तो व उच्च शिक्षितों द्वारा, साहूकारों, करदाराओं व उच्च शिक्षितों को दिया गया। यह सभ्यता समय बायुशिक्ल दस प्रतिशत छु अधिक बैठती थी। परन्तु 1946 में भारत का संविधान जाना शुरू हुआ तो इसमें लाल कमटी की लगभग सभ्यता सिफरिशों का समाप्त हुआ। संविधान लिखने वाले डा. बाबा ब अब्दुल करक ने गांधी का विरोद्ध लेकर ही संविधान लिखा, जिनके उनके खूब वैज्ञानिक मनमेंद्री जगह पर थे, मगर बाबा साहूकारों जी के इस सिद्धान्त से पूरी सहमत थे कि भारतीय विवरन में एक राजा—महाराजा जो राजनीतिक अधिकार मिले तो राजनीतिक खींचने वाले और मैं योजना बनायी तो तराजीक खींचने वाले वारेबाबर ही हो। अतः भारतीय धान में एक समान मताधिकार बनानु बनाया गया और सिद्धियों साहूकारों व महाजनों और महाराजाओं को तराजीक जीवन जीने वाले ने नये भारत का 'राजा' बोट अधिकार के माध्यम से बनाया। अतः भारत के लोगों को मिले एक बोट की कोई कीमत नहीं जा सकती। मगर भारत चुक्के न्न धर्मों को मानने वालों व न्न जटियों व संस्कृतियों और

तदाताओं की धार्मिक व जातिगत प्रवृत्ति की सामाजिक पद्धतान को अपने रख कर बोटों की गोलबद्दली और उनके प्रयास से संतुष्ट होकरन्तर्याम व्यक्तिगत रूप से मतदाता सशक्तिकरण की बात करते हुए इसके भजबूत बनाने की बात रता है और यह काम हर चुनाव में लोगों के साथ आया तभी अपनी में आये दलवाल का जापाना लेकर कर सकता है। इसके लिए उस सत्ता पर पिछले दो वर्ष साल से काविज रही पार्टी की रक्कार के कामों का आकलन करके इसना पड़ता है। इसका मूलभूत विषय राष्ट्रियता, गणीती का विश्वास हांगाई, रीजरार, स्वास्थ्य व उसकी अमदानी में आनुपातिक इजाफा होता है। हम देख रहे हैं कि पिछले एक वर्षीने से इन दो राज्यों से सेवत कुल लोगों व राज्यों के विभिन्न महासाना लोग रहा है और भाजपा व कांगड़े नेता अपना-अपना विर्माण खड़ा करने की काशिश कर रहे हैं। मगर व बुनाव प्रचार बद्द भी चुका है और जनता मन बना चुकी है कि इसे किस पार्टी को जिताना है और उसके द्वारा चुनावों को जीता होता है। चुनावों में वर-जीत का भी सिद्धान्त होता है जिस पार्टी की चुनावी विर्माणों को पापन्द आता है वही पार्टी जीत जाती है। मगर ऐसा करने के लिए उसको हातों में भी किए अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने बोट व इर्टेमाल करने के लिए मतदान न्द्र तक जायें। अब हम इन ज्यों की जनता से केवल यही जीत जाएगी तो वही कि अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने बोट स मायामें भी हमारे देश के दो बहुत आगे रहते हैं जहाँ मतदान

वोट की कोई कीमत नहीं !

अखिलेश यादव की चुनावी तैयारी
देखकर उड़ सकती है भाजपा की नींद



खता-कर्ताना मैं सबसे ज्यादा विकास दर वाले मध्य प्रदेश में कांगेंस की उपेक्षा से क्या समाजावापनी पार्टी ने मान लिया है कि अगले आम चुनाव में उसे अकेले अपने दम पर ही उतारना होगा? अखिलेश यादव ने आगे बढ़कर अपने असर वाले उत्तर प्रदेश में जिस तरह हारना चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, उसके संकेत तो यही हैं। चुनाव में जीत-हार बाद का मसला है, लेकिन अखिलेश की तैयारियों से साफ़ है कि अगर गठबंधन की ओरडी मुंजाइश बनी भी तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन उनकी ही शर्त पर होगा। अखिलेश जिस तरह जुटे हुए हैं, उससे लगता है कि अगर गठबंधन नहीं भी होता तो भी हां तक लिए गए बदाया। लाकन जिस तरह मध्य प्रदेश में कांगेंस ने उन्हें किनारे पर छोड़ा वे नाराज हैं। अखिलेश अपनी नाराजगी जाहिर करने से नहीं हिचकते। कमलनाथ के बगान के बाद जिस तरह अखिलेश ने तीव्र प्रतिक्रिया जारी, उससे साफ़ है कि कांगेंस को लेकर इस बार वे सहज नहीं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चुनावी देने के लिए वे कांगेंस का साथ ले सकते हैं। लेकिन कांगेंस का जैसा सर्व या है, जिस द्वारा नियमनसभा चुनावी में कांगेंस ने गठबंधन में शामिल दलों को अनदेखा किया है, इसलिए वे कांगेंस के साथ भी भरे मन से * * *

इंजिनियर आर्ट युद्ध अपराध

गाजा में हमास की संसद पर इजराइली सेना ने कब्जा कर लिया है औ वहां अपना झांडा भी फहरा दिया है। हमास के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इजराइली से एक आईडीएफ को रोक सके। गाजा में बारों तरफ अराजकता का माहौल है। नागरिक हमास के टिकानों को लूट रहे हैं। हमास के लड़ाक दक्षिण की ओर भाग रहे हैं। युद्ध वें अब तक 11 हजार से ज्यादा फिलस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। जबकि 1400 के लगभग इजराइली मारे जा चुके हैं। गाजा के नागरिकों का अब हमास की सरकार में कोई विश्वास नहीं रहा है। हमास की संसद यानि फिलस्तीनी विधान परिषद वे हमास के नियंत्रण में था जिसमें अब इजराइली सैनिक बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले इजराइल ने कहा था एक कर्मजों को दो दिल्लिं उत्तर और दक्षिण में बांट दिया गया है। उत्तर गाजा की सड़कों पर दर्जनों शव पढ़े हुए हैं। अस्पतालों को भी इजराइल ने निशाना बनाया है। ऊल-कूदस अस्पताल और ऊल-शिफा अस्पताल में हमलों के चलते मासूम बच्चे मारे गए हैं। अस्पताल कब्जाह करने वाले हैं। इजराइल का आपात्काल है कि इन अस्पतालों के नीचे हमास के लड़ाकों का कमान सैटर है। इजराइल का कहना है कि वह आपात्काल की कहना है और वह बंधनों की सुरक्षित रिहाई के तरफ युद्ध जारी रखेगा। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि इसमें इजराइली बंधनों की रिहाई के लिए तैयार हो गया है।

के और अधिक सदस्यों के बीच में शामिल होने का जोखिम रहेगा। इजराइल और लेबनान सीमा पर धीरे-धीरे तटवार आज रहा है। न तो इजराइल न ही हिंजुल्लाह आर-पार लड़ाई चाहता है। मध्यपूर्व के सम्प्रदाय वाले देश मिस्त्र, इरान अमेरिका के साथ हैं। गाजा के खिलाफ सलकी अरब के में मुस्लिम देशों के नाताओं बैंक में तुरंत संघर्ष विरास फिलस्तीनी मुद्दे के समाधान मांग की गई। सलकी अरब के गोहम्मद बिन सलमान ने रसीद्धीय मानवाधिकार कानूनों पुष्ट करने वाले नानदंडों पुष्ट उठाते हुए पश्चिमी देशों खामोशी की आलोचना की। न जब ईरानी राष्ट्रपति और अन्य देशों ने इजराइल और कोहे सहायी देशों को तेल की इसी रोकने तथा राजनयिक संबंध तोड़ने का प्रताप है तो इस प्रस्ताव का विरोध कुड़ा। इसका अर्थ यही है कि नम देश भी एकमात्र नहीं थे। अब अमीरीका और बहरीन न कुछ देशों ने इस प्रस्ताव को रोका कर दिया। संयुक्त अरब राष्ट्र और बहरीन ने 2020 में इराइल के साथ राजनयिक संबंध बाल किए थे। अब लीग के देश ऐसे हैं जिनके इजराइल के साथ आर्थिक संबंध हैं। ऐसे में गाजी देश इजराइल पर कोई भी

हाता है।” जून 1967 के युद्ध में विश्विमी किनारे, पूर्णी युश्यलम और अप्रियिकी की गोलान की फाईड़ियों के बीच लड़ाई के दौरान साथ-साथ गाजा पर इजराइली फौजें कठोर के साथ यह पढ़ी इजराइल के लिए सुरक्षा की समस्या बन गई। अब फिर गाजा में रहने वाले आधी लोग शरणार्थी बन चुके हैं। ह स्पष्ट है कि बहुत बड़ी मानीवीय असदी पैदा हो चुकी है। बड़ी संख्या की शरणार्थी को दफनाने के लिए जैमीन गड्ढे खोदे जा रहे हैं। बेघर हुए आधी लोगों के पुनर्वास के लिए ऐसी पहल नहीं की जा सकी। इन लोगों को किसी से बसाने के लिए उनपर पहल कराया। खतरनाक जीवी की जंग में युद्ध अपराध ही रहे हैं। 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध आ। इस युद्ध में साड़े पांच करोड़ ज्यादा लोग मारे गए। इस विश्व युद्ध में पहले पश्चात् बम का इस्तेमाल आ। ऐसी तबाही फिर न हो इसे जेनेवा के लिए 1949 में जेनेवा म्मेलन में युद्ध के नियम बनाए गए। इसमें तय किया गया कि युद्ध के दौरान आम नागरिकों को बराबर नहीं बनाया जा सकता। दूसरी याशी इलाकों, स्कूलों, कालेजों और अप्सत्रालों को निशाना नहीं बनाया जा सकता। आम नागरिकों के लिए बनाए गए कैम्पों पर भी बसला नहीं किया जा सकता तेकिन जराइल ने सभी सीमाएं तड़ दी। और बानवत कराह रही है। मास के आतंक का खायिजा यास नागरिकों को भगताना पड़ गया।

छोड़कर अखिलेश यादव ने गठबंधन की गुंजाइश तो छोड़ी है। अखिलेश के साथ विधानसभा चुनाव लड़ चुके सुहृदलदेव भारतीय समाज पार्टी के आमप्रकाश राजभर अखिलेश का साथ छोड़ कर चुके हैं। जिस तरह बहन की मायावती ने जिस तरह 'एकला चलो रे' का राग अपना रखा है, उससे अखिलेश मान चुके हैं कि बहुजन समाज पार्टी से इस बार गठबंधन संभव नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में दानों पार्टियों के बीच गठबंधन था। तब इसे 'बुआ-बुआ' का गठबंधन माना जा रहा था। साल 2017 के विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव की पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन था, तब उस गठबंधन को राहुल गांधी के साथ के बलते 'यूपी' के लड़के कहा गया था। वैसे तो हर चुनाव में हर राजनीतिक दल के लिए गुंजाइश होती ही है।

लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि देश में अतीत में ये दानों गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के समाने काम नहीं आए। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का सफां गठबंधन नहीं था। लेकिन यह भी सच है कि समाजवादी पार्टी ने अमीरी और रायपुरेली में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। लगता है कि पिछले दो विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों के अनुभव से अखिलेश खीखेन की कोशिश कर रहे हैं। वेंगली नीतीश कमारा और नीतीश कमारा का लोकशास्त्र अब भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखा है। अखिलेश की निगाह गैर जाटव दलित और गैर यादव पिछड़ी जातियों पर भी है। चूंकि राजभर और नोनिया जातियों साथ आती रही हैं और अमप्रकाश राजभर अब भारतीय मजबूरी में ही विहृत से तैयारी करते नजर आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्से चौकटी लगायी।

प्रात्येकी देश में उत्तराखण्ड है गान्धीविक उत्तराखण्ड चीन और पाकिस्तान दीर्घों की उत्तर कारों है जिनकी दूरी 2

की बदले को कारबैग्ज से ज्यादातर लोग निर्वेष आग फिलस्टीनी नामरिक है। यह युद्ध पहले की लड़ाइयों से अलग है। यह युद्ध ऐसे वक्त में छिड़ा है जब मध्यपूर्व के करणे वाली रेखाओं के टट्टने की गज़ सुनाई दे रही है। पिछले दो दशकों में बिखरे हुए मध्यपूर्व के राजनीतिक परिदृश्य में सबसे गमीनी विभाजन इरान के मिश्र देशों और अमेरिका की लास्योनी देशों के बीच देखा गया है। अक्सर प्रतिरोधी की धरी कह जाने वाले 'ईरानी नेटवर्क' में लेबनान का हेजुल्लाह, सीरिया की बराबर अल-असद द्वारा, यमन के हुथी विद्रोही और इराकी मिलिशिया शामिल हैं। इराकी मिलिशिया को ट्रेनिंग और हथियार दोनों ही इरान से मिलते हैं। इरान गाजा पट्टी में हमास और किलस्तीन इस्लामी जिहाद की भी पुरजोर समर्पण करता है। हिन्दी और, इरान रुस और चीन से भी अपनी नज़दीकियां बढ़ा रहा है। यूक्रेन में चल रहे रुस के युद्ध में इरान एक महत्वपूर्ण भागीदार बन गया है। चीन इरान से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है। जब जामा मात्रा में युद्ध जारी रहेगा, और जब तक इजराइल फिलस्टीनी लोगों को मारना और उनके घरों को बर्बाद करने वाला देश था।

बांग्लादेश में 7 जवारी को संसदीय चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री के इसीना की मांग थी कि लेकर विधायी दलों के विरोध प्रदर्शन ने देश को हिलाकर रख दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त हबीबुल अवल ने एक लाइव टेलीविजन प्रसारण में जानकारी देते हुए बताया कि 12वां संसदीय चुनाव 7 जनवरी को 300 सीटों पर होगा। उहोने पार्टीयों से राजनीतिक संकट को डब करने के लिए बातचीत करने का आग्रह किया। मुख्य चुनाव बांग्लादेश ने शनिवार से पार्टी (बीएनपी) के वीर्ष नेता या तो जेल में हैं या निर्वासन में हैं। बीएनपी ने पहली ही कहा है कि अगर प्रधानमंत्री शेष हसीना इस्तीफा देती है और सामाजिकी की देखारेख के लिए एक गैर-प्रवासीपूर्ण कार्यवाचक सरकार को सत्ता हस्तांतरित नहीं करती है तो वह चुनावों का बहिष्कार करेंगे। जब सत्रत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण की बात आती है तो तत्काल बांग्लादेश ने भी इसी तरह का पैट्रैन अपनाया है। राजनीति में तख्तापलट, जवाबी

तख्तापलट, हत्याएं और सैन्य शासन लागू किया गया है, जिससे देश टकराव, चुनावी दिनों, विपक्ष के प्रति असंतुष्टियां और हड़ताल (बंद) की राजनीति की ओर बढ़ रहा है। कैरी है बांग्लादेश के संसद की रुपरेखा।

1971 में पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश ने 1972 में खुद का संविधान बनाया। इसके बाद यहाँ संसदीय व्यवस्था लागू हुआ। बांग्लादेश के संसद को जातियों संगमरम्ब या हातून औफ द नेशन बांग्लादेश का जाता है। सरकार के अनुसुन्दर इसकी नई इमारत 15 फरवरी 1982 में तैयार हुई और 200 एकड़ में बनी है। बांग्लादेश में संसद की 350 सीटों के लिए चुनाव कराया जाता है। बांग्लादेश की संसद में लिमांओ के लिए 50 सीटें रिजर्व हैं। संसद में सत्ताधारी दल के नेता प्रधानमंत्री बनते हैं और वे ही कार्यकारी प्रधान होते हैं। 2009 से ही बांग्लादेश की सत्ता में शेष हसीना की पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग का बजाएगा।

15 सालों से शेष हसीना का शासन हसीना ने पिछले 15 वर्षों से

बांग्लादेश का नेतृत्व किया है और उन पर कठोरता से शासन करने का आरोप लगाया गया है। अगर विषया के बहिकार जारी रखा तो उनकी चौथी बार सत्ता में लौटना लगभग तय माना जा रहा है। हफ्तीना की मुख्य प्रतिवृद्धी और दो बार की प्रधानमंत्री, बीएनपी नेता खालिदा जिया प्रधानी रूप से घर में रहने वाले हैं, जिसे उनकी पार्टी फर्जी भ्रष्टाचार के आरोप कहती है। बीएनपी ने 2014 के चुनावों का बहिकार किया, लेकिन 2018 में भाग लिया। मुस्लिम-बहुल देश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी जगत-ए-इस्लामी और इस्लामी एजेंलेन बांग्लादेश (आईएबी) पार्टी ने भी कहा कि वे चुनावों को अवृक्त कर देंगे।

मंत्री ने रखा अपना पक्ष विपक्ष क्षेत्र कर रखा विरोध विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (वीएनपी) सात जनवरी के आम चुनावों को रख करने की मांग करते हुए 48 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड्डताल का आठवाहन किया। विपक्ष ने साथ ही दावा किया कि इस चुनाव का उद्देश्य प्रधानमंत्री शेख हसीना का सत्तारूढ़ अवामी शासकरार को लगातार बौद्ध कार्यकाल के लिए सत्ता में लाना है। यह घोषणा मुख्य चुनाव अयुक्त काजी हसीनुल अबल के उपर बाहर के एक दिन बाद आयी है जिसमें कहा गया था कि बहुप्रतीक्षित अमीर चुनाव 7 जनवरी को होगा। बीएनपी के वरिष्ठ संस्कृत हास्ताचिव रुहुल कबीर रिजीबी ने सुबह 6 बजे से दो दिवसीय विपक्षी ने सुबह 6 बजे से ही आठवाहन का आठवाहन किया बांग्लादेश के चुनाव पर क्यों है भारत, चीन और पाकिस्तान के निगम हैं पांच साल बाद हो रहे बांग्लादेश के चुनाव पर भारत, पाकिस्तान और चीन की नज़र जमी हुई है इसे तीनों देशों के लिए काफ़ अस्त्र नहीं बल्कि यह राह ही है। बांग्लादेश के गठन के बाद से ही भारत उसका महत्वपूर्ण दोस्त रहा है। दोनों देश अपी भी कई मोर्चे पर एक भूमिका में हैं क्षेत्रीय साझेदार की जागीरदारी दाका में बड़ी सख्ती में बीजी प्रवासी रह रही है। चीन बीआरआई प्रोजेक्ट के जरिए भी लगातार बांग्लादेश में अपनी उपरिक्षित बढ़ा रही है। 2018 में चीन ने बांग्लादेश के साथ साझेदारी का घोषणा किया था। वही शेख हसीना अग्रणी सत्ता में फिर से वापर्सी करती हैं, तो पाकिस्तान के लिए आगे की राह आसान नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान को खालिदा जिया की पार्टी से मिमीद है। अग्रणी खालिदा जिया सरकार और बीएनपी तो कई मोर्चे पर दोनों देश फिर से साझेदारी कर सकता है।

